

prices. On the whole, the supply position of the decontrolled categories continues to be easy and prices are not appreciably higher and, therefore, the aim of decontrol has not failed.

(c) No, Sir.

**Cement**

- \*277. {  
 Shri Hem Raj:  
 Shri M. L. Dwivedi:  
 Shrimati Savitri Nigam:  
 Shri S. C. Samanta:  
 Shri Onkar Lal Berwa:  
 Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of Industry and Supply be pleased to state:

(a) the quantity of cement produced in the country during 1962-63, 1963-64 and the second quarter of 1964 and the quantity that was exported during this period; and

(b) what are the needs of the country and what is the shortage?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra):

(a) Production of Cement

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1962-63 :         | 8,850,000 tonnes |
| 1963-64 :         | 9,425,000 tonnes |
| April-June 1964 : | 2,328,000 tonnes |

Exports of Cement

|           |               |
|-----------|---------------|
| 1962-63 : | 42,000 tonnes |
| 1963-64 : | 71,000 tonnes |

(Figures rounded off to the nearest thousand tonnes).

7,416 tonnes were exported during April 1964; no exports took place during the months of May and June, 1964.

(b) There is still a considerable disparity between the demand for cement in the country and the available supply. The current shortage is estimated to be in the region of 2 million tonnes per annum.

**मैसूर में अल्युमीनियम का संयंत्र**

- \* 278. {  
 श्री वासुधा :  
 श्री हिम्मत्सिंहका :  
 श्री रामेश्वर टाटिया :  
 श्री बचन :  
 श्री भी० प्र० यादव :  
 श्री बिशानचन्द्र सेठ :

क्या इस्पात और खान मंत्री 14 फरवरी, 1964 के घताराफित प्रश्न संख्या 191 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच मैसूर राज्य में अल्युमीनियम संयंत्र की स्थापना के लिये तथा महाराष्ट्र राज्य में अल्युमीनियम की एक नई मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों कारखानों की, प्रत्येक की अलग अलग क्षमता क्या होगी और परिबोधनाओं का अनुमानित पूंजी विनियोजन क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री लंजीब रेड्डी) : (क) और (ख). कलकत्ता की अन्तर्जातिक लेब की एक फर्म, इण्डियन एल्युमिनियम कम्पनी लि०, के नाम मैसूर राज्य में 30,000 वार्षिक मीट्रिक टन की क्षमता के एक एल्युमिनियम प्रदायक संयंत्र की स्थापना के लिये तथा महाराष्ट्र राज्य में 13,000 वार्षिक मीट्रिक टन की क्षमता की एक नई एल्युमिनियम बेलन-मिल स्थापित करने के लिये "प्रायव-वर्क"